Toppersnotes®
Unleash the topper in you

UPPSC - CSE

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा

Prelims & Mains

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज

सामान्य अध्ययन

पेपर 3 – भाग 1

भारतीय अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

पेपर - 3 भाग - 1

भारतीय अर्थव्यवस्था

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	**भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास** • ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था • ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था • स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था • नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था	1

2.	**अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत**
	• सूक्ष्म और स्थूल अर्थव्यवस्था
	• आर्थिक प्रणाली
	• अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
	• माँग आपूर्ति प्रबंधन
	• आपूर्ति क्या है?
	  ○ आपूर्ति के निर्धारक
	  ○ आपूर्ति की लोच
	• बाजार संतुलन
	• मांग और आपूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव
		5

3.	**राष्ट्रीय आय**
	• राष्ट्रीय आय के पहलू
	  ○ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
	  ○ शुद्ध घरेलू उत्पाद(NDP)
	  ○ सकल राष्ट्रीय उत्पाद(GNP)
	  ○ सकल राष्ट्रीय उत्पाद(NNP)
	• राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके
	• आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति
		11

4.	**धन और पैसे की आपूर्ति**
	• धन का विकास
	• धन के कार्य
	• धन का वर्गीकरण
	• धन के प्रकार
	• क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन
	• मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक समुच्चय
	  ○ मुद्रा बाजार
	  ○ संगठित क्षेत्र
	  ○ असंगठित क्षेत्र
	  ○ धन की आपूर्ति
		16

	○ धन गुणक ○ मौद्रिक समुच्चय • वित्तीय प्रणाली • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन	
5.	**मौद्रिक नीति** • मात्रात्मक उपकरण • गुणात्मक उपकरण • मौद्रिक नीति समिति ○ उर्जित पटेल समिति	**23**
6.	**भारत में बैंकिंग** • वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) • भारत में बैंकों का विभाजन • विशिष्ट बैंक • गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) • NBFC के रूप में पंजीकरण करने की शर्तें • बैंकिंग क्षेत्र में सुधार ○ नरसिम्हम समिति-द्वितीय (1998) ○ नचिकेत मोर समिति (2013) ○ पीजे नायक समिति (2014) ○ बेसल मानदंड • दिवाला और दिवालियापन • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष • वित्तीय समावेशन • स्वर्ण निवेश योजनाएं	**28**
7.	**मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र** • मुद्रास्फीति के कारण • मुद्रास्फीति के प्रकार • WPI बनाम CPI • उत्पादक मूल्य सूचकांक(PPI) • आवास मूल्य सूचकांक • सेवा मूल्य सूचकांक (SPI) • मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण • मुद्रास्फीति के प्रभाव • व्यापारिक चक्र • आर्थिक सुधार	**48**
8.	**भारत में बेरोजगारी** • भारत में बेरोजगारी का उपाय • भारत में बेरोज़गारी के प्रकार • भारत में बेरोज़गारी के कारण • बेरोज़गारी का प्रभाव • सरकार की पहल ○ जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	**56**

	○ ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (TRYSEM) ○ ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ○ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ○ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ○ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	
9.	**गरीबी** • गरीबी के प्रकार ○ लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक • भारत में गरीबी का आकलन • गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न समितियों की अनुशंसाएं • रंगराजन समिति • भारत में गरीबी के कारण • भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम • बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	**60**
10.	**भारत में वित्तीय बाज़ार** • मुद्रा बाजार ○ भारत में मुद्रा बाजार के अवयव ○ संगठित क्षेत्र ○ असंगठित क्षेत्र ○ म्यूचुअल फंड्स ○ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) ○ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड • पूंजी बाजार ○ परियोजना वित्तपोषण ○ वित्तीय संस्थाएं ○ विशिष्ट वित्तीय संस्थान (SFI) ○ सम्बंधित उद्योग • वित्तीय विनियमन ○ नियामक संस्थाएं ○ पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ○ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ○ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ○ अर्ध-विनियामक एजेंसियां • विभिन्न नियामक • केन्द्रीय मंत्रालय • कुछ वित्तीय मध्यस्थों के लिए विशेष क़ानून	**65**
11.	**भारत में प्रतिभूति बाजार** • प्राथमिक और द्वितीयक बाजार • शेयर बाजार • राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज • स्टॉक एक्सचेंजों में खिलाड़ी • भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) • उत्पाद व्यवसाय	**71**

	• स्पॉट एक्सचेंज • शेयर बाजार की महत्वपूर्ण शब्दावली • विदेशी वित्तीय निवेश • सहभागी नोट (पी-नोट्स, या पीएन) • बचाव निधि(Hedge Fund) • क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (CDS) • प्रतिभूतिकरण(Securitization) • भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड • गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स • केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई ईटीएफ) • पेंशन क्षेत्र में सुधार • अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट	
12.	**बाहरी क्षेत्र और भुगतान संतुलन** • महत्वपूर्ण परिभाषाएं • भुगतान का संतुलन • मुद्रा प्रकार • विदेशी निवेश • बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) • व्यापार संवर्धन • निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं • नई विदेश व्यापार नीति 2021-2026 • बैंकिंग पूंजी लेनदेन • मुद्रा परिवर्तनीयता • विदेशी कर्ज • भारत में विनिमय दर प्रबंधन • व्यापार संतुलन	**81**
13.	**अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान** • ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष • विश्व बैंक • अन्य वस्तु व्यापार समझौते • भारत और विश्व व्यापार संगठन • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक • एशियाई विकास बैंक • आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	**95**
14.	**भारतीय सार्वजनिक वित्त** • सार्वजनिक राजस्व • सरकारी व्यय • सार्वजनिक ऋण • राजकोषीय नीति • राजकोषीय नीति बनाम मौद्रिक नीति ○ राजकोषीय नीति के प्रकार ○ विकास	**106**

	• घाटा
	  ○ घाटे के प्रकार
	• राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय
	• सार्वजनिक ऋण
	  ○ राज्यों को केंद्रीय स्थानांतरण
	  ○ राज्य वित्त	

15.	**बजट बनाना**
	• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
	  ○ बजट के प्रकार
	  ○ बजट घटक
	  ○ प्राप्तियां
	  ○ व्यय
	  ○ विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय
	  ○ योजनागत और गैर-योजनागत व्यय
	  ○ बजट में डेटा
	• बजट के अधिनियमन की प्रक्रिया
	  ○ बजट 2021
	• भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा:
	  ○ आर्थिक सर्वेक्षण 2021
	• सरकारी खाते
	• घाटा वित्तपोषण
		114

16.	**कराधान**
	• कराधान के पीछे उद्देश्य
	• कराधान के तरीके
	• कर के प्रकार
	  ○ प्रत्यक्ष कर
	  ○ अप्रत्यक्ष कर
	• कर सुधार
	• राजा चेलिया समिति
	• केंद्र से राज्यों को फंड ट्रांसफर
	• कराधान में महत्वपूर्ण शर्तें
	• लाफ़र वक्र
	• अंतर्राष्ट्रीय कर संधियाँ
		118

17.	**अनुदान** • कृषि अनुदान की आवश्यकता • अनुदानों का वर्गीकरण • संवितरण के विभिन्न तरीके • भारतीय खाद्य निगम (FCI) • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 • विश्व व्यापार संगठन और कृषि अनुदान	**131**
18.	**बुनियादी ढाँचा** • अवसंरचना विकास • उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना।	**135**

	• व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) • सड़कें • भारतमाला परियोजना • रेलवे ○ रेलवे सुधारों पर विवेक देबरॉय समिति ○ समर्पित माल ढुलाई गलियारे • बंदरगाह ○ सागरमाला ○ तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZs) • हवाई अड्डे ○ UDAN-क्षेत्रीय संपर्क योजना • औद्योगिक गलियारे • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) • मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क • बिजली क्षेत्र • तेल और गैस क्षेत्र • ऊर्जा सुरक्षा ○ जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 • जैव ईंधन ○ इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम • स्मार्ट सिटी, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) • सभी के लिए आवास • एनआईआईएफ (राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष) • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन	
19.	**निवेश मॉडल** • स्रोत • निवेश मॉडल के प्रकार	**149**
20.	**उद्योग** • 1991 से पहले की औद्योगिक नीति • 1991 के बाद की औद्योगिक नीति • विनिवेश के प्रकार • व्यापार सुगमता • औद्योगिक विकास के चरण • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) • सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम, 2008: • खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) • क्षेत्रीय चिंताएं • स्टार्ट-अप इंडिया	**151**
21.	**आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण** • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) • आपूर्ति श्रृंखला योजनाएं • आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना	**162**

	• खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)	
22.	**भारत में भूमि सुधार** भूमि सुधार के लिए तर्क • भूमि सुधार के घटक • भूमि सुधारों का प्रभाव • भूमि सुधार • भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 • भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में समस्याएं • सामाजिक प्रभाव आकलन	**167**
23.	**आर्थिक सुधार** • 1991 आर्थिक संकट • 1991 के सुधार • भारत में आर्थिक सुधार • सुधार के उपाय • आर्थिक सुधारों की पीढ़ी • मिश्रित अर्थव्यवस्था	**174**
24.	**भारत में योजना** • स्थानीय योजना • राष्ट्रीय योजना • योजना के प्रकार • योजना के प्रमुख उद्देश्य • भारत में योजना का विकास • राष्ट्रीय विकास परिषद • पंचवर्षीय योजनाएं • NITI (नीति) आयोग	**179**
25.	**बीमा** • भारतीय जीवन बीमा निगम (LICI) • भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) • भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (AICIL) • बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)। • पुनर्बीमा • जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम • क्रेडिट गारंटी फंड • एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECGC) • राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) • बीमा प्रवेश और सघनता • नीतिगत पहल ○ नई सुधार पहल • नई बीमा योजनाएं	**186**
26.	**वृद्धि, विकास और खुशहाली** • आर्थिक संवृद्धि • आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक	**191**

	• आर्थिक विकास
	  ○ आर्थिक संवृद्धि और विकास के बीच अंतर
	• असमानता
	• खुशहाली
	  ○ निज और सार्वजनिक नीति
	• समावेशी वृद्धि और संबंधित मुद्दे
	• भारत में निर्धनता आकलन
	• जनसांख्यिकीय विभाजन
	• भारत में श्रम कानून
	• औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था
	• सतत विकास लक्ष्य (SDGs)	

27.	**कृषि**
	• पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि का विकास
	• कृषि एवं हरित क्रांति
	• भूमि उपयोग से संबंधित शर्तें
	• कृषि विपणन
	• सार्वजनिक वितरण प्रणाली
	• निवेश प्रबंधन योजनाएं/मिशन
	• जल प्रबंधन-सूक्ष्म सिंचाई
	• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
	• कृषि साख
	• खाद्य सुरक्षा
	• उत्पादन प्रबंधन योजनाएं
	• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
	• प्रधानमंत्री आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान)
	• उत्पादन प्रबंधन योजनाएँ
	• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
	• कृषि निर्यात नीति 2018
	• मूल्य स्थिरीकरण के उपाय
	• कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर
	• कृषि में विस्तार प्रबंधन
	• कृषि विस्तार के लिए जनसंचार माध्यमों का समर्थन
	• संबद्ध गतिविधियों का प्रबंधन-अतिरिक्त आय अर्जित करना
	  ○ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rkvy)
	  ○ कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना (ICAR-ARYA)
	  ○ पहले किसान (आईसीएआर)
	  ○ पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (ICAR)
	  ○ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY)
	  ○ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
	  ○ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)
	  ○ नई रोशनी योजना
	  ○ प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
		203

प्रिय विद्यार्थी, टॉपर्सनोट्स चुनने के लिए धन्यवाद।

नोट्स में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करने लिए टॉपर्स नोट्स ऐप डाउनलोड करे ।

ऐप डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश देखे :-

ऐप इनस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या गूगल लेंस से QR स्कैन करें ।

टॉपर्सनोट्स एग्जाम प्रिपरेशन ऐप

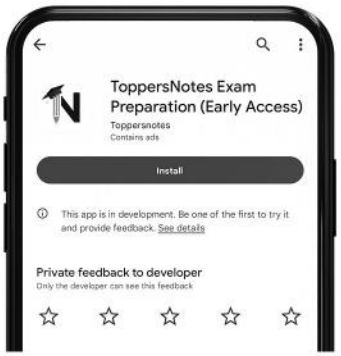

टॉपर्सनोट्स ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ।

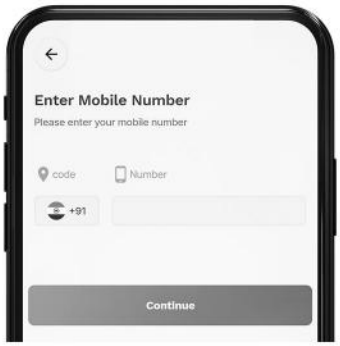

लॉग इन करने के लिए अपना **मोबाइल नंबर** दर्ज करें ।

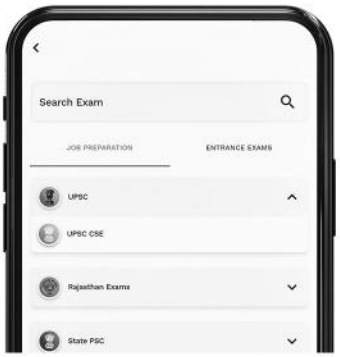

अपनी **परीक्षा श्रेणी** चुनें ।

सर्च बटन पर क्लिक करें ।

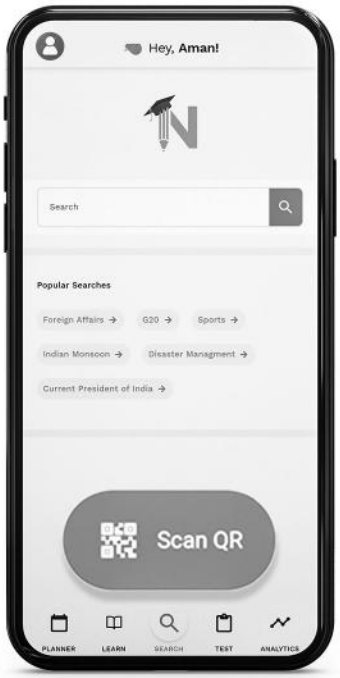

SCAN QR पर क्लिक करें ।

किताब के **QR कोड को स्कैन** करें ।

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए
hello@toppersnotes.com पर मेल करें
या **766 56 41 122** पर whatsapp करें ।

Thank You!!

for Choosing Toppersnotes

50% OFF

Just for you!!

USE CODE : **TOPPER50**

Coupon valid only for 30 days after purchase.

Scan the QR code and login from your registered phone number

UPPCS TEST SERIES

~~₹1499~~ ~~₹999~~ **₹499**

(After coupon)

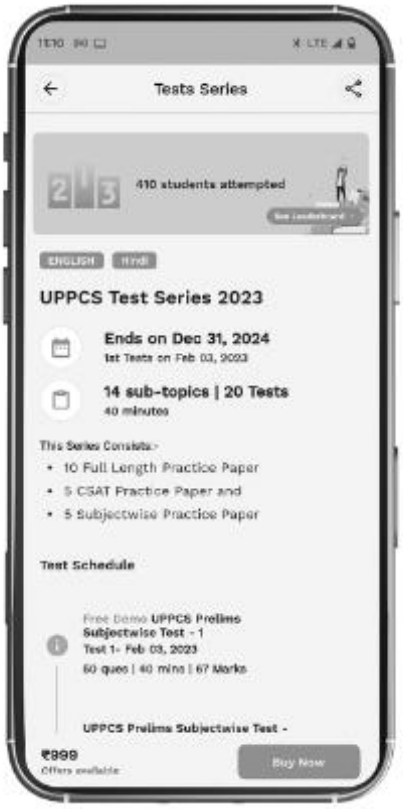

- 5 Subject-wise Test
- 10 Full Length Test
- 5 CSAT Test
- Based on Latest sylabus.
- Up Centric question according to new pattern
- Bilingual
- Comprehensive coverage
- High-quality questions
- Detailed explanations
- Performance analysis
- Flexibility - At your own pace
- Peer comparison on leader board
- Affordable pricing
- Designed by Toppers and top faculty.

How to use the Coupon Code?

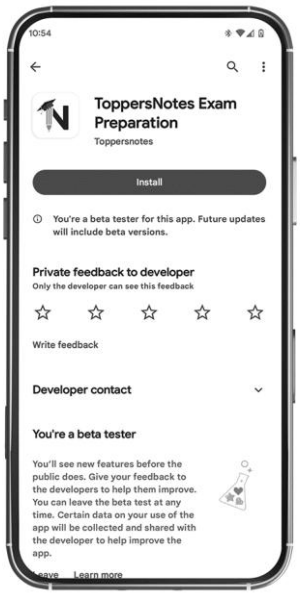

STEP:1

Scan the QR code from the back page and install the Toppersnotes learning app.

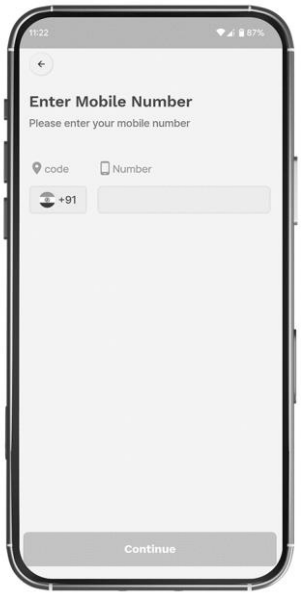

STEP:2

login with your registered phone number and select your exam.

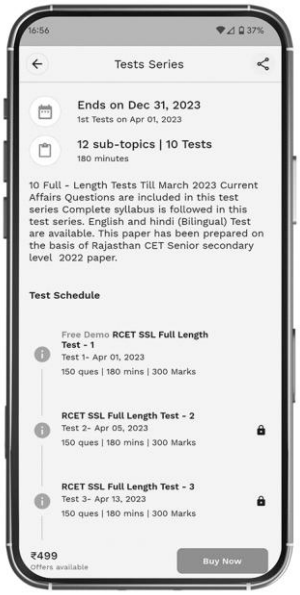

STEP:3

On the test series page you can try demo test or Click on buy now

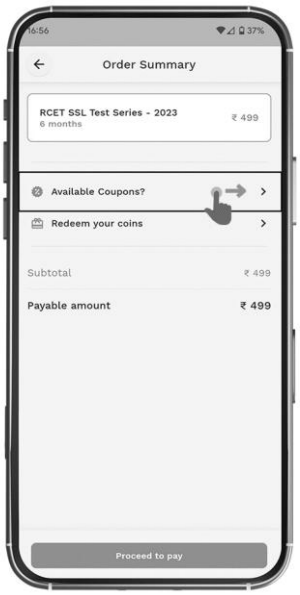

STEP:4

Click on apply coupon

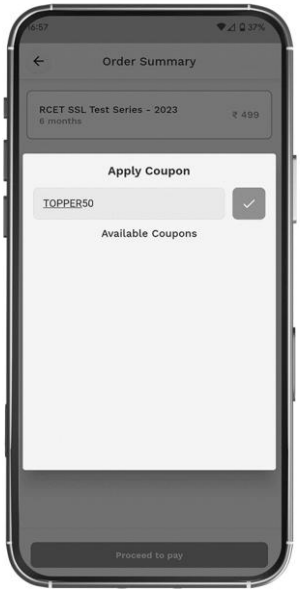

STEP:5

Enter the coupon code.

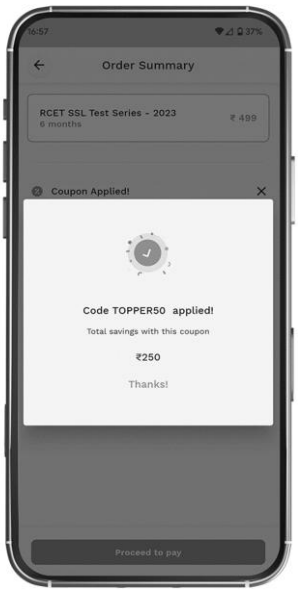

STEP:6

Your code will be applied and then proceed with the payment.

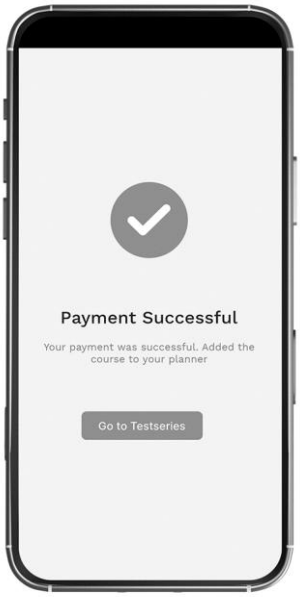

STEP:7

After successful payment click on go to test series

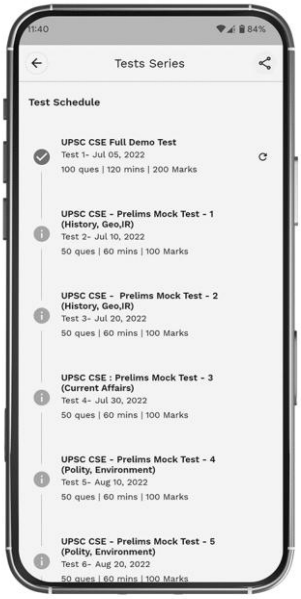

STEP:8

Your test series subscription is active now

For any technical support or queries call

9614-828-828

Email

apps@toppersnotes.com

1
CHAPTER

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

स्वतंत्रता पूर्व अवधि	• उत्पादन या उत्पादकता स्तरों की संरचना में थोड़े से बदलाव के साथ, लगभग ठहराव की अवधि।
1930 के दशक के मध्य	• राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को देखा। • भारत एक विदेशी देश, यूनाइटेड किंगडम के लाभ के लिए विकास का अनुसरण कर रहा था।
स्वतंत्रतापूर्व संध्या पर भारत की आर्थिक रूपरेखा	• औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक उत्कृष्ट परिदृश्य पूरी तरह अस्त-व्यस्त था। • कृषि और विनिर्माण दोनों में मूलभूत समस्याएँ थीं, जिसमें सरकार केवल एक न्यूनतम भूमिका निभा रही थी।

ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था

- **प्रकार:** स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी।
- **कृषि:** अधिकांश लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत
  - विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियों की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था।
  - **उदाहरण:** सूती और रेशमी वस्त्रों के क्षेत्र में हस्तशिल्प उद्योग।
  - धातु और कीमती पत्थर के काम आदि।
- **बंगाल:** वस्त्र उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध - मलमल का कपड़ा
- भारतीय उत्पादों में इस्तेमाल की गई सामग्री की अच्छी गुणवत्ता और यहाँ से अधिकांश आयातों में देखे जाने वाले शिल्प कौशल के उच्च मानकों के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठा मिली।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था

कृषि क्षेत्र	• अर्थव्यवस्था का प्रकार: मूल रूप से कृषि प्रधान
	• लोगों की भागीदारी: देश की लगभग 85% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी।
	• कृषि उत्पादकता कम हो गई, खेती के तहत कुल क्षेत्र के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई।
	• कृषि क्षेत्र में स्थिरता के कारण
	  ○ अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई भूमि बंदोबस्त प्रणाली: बंगाल में लागू की गई ज़मींदारी प्रणाली ने कृषि क्षेत्र से होने वाले लाभ को काश्तकारों के बजाय जमींदारों को दे दिया।
	  ○ प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर।
	  ○ सिंचाई की सुविधा का अभाव।
	  ○ उर्वरकों का नगण्य उपयोग।
	• नकदी फसलों की खेती में वृद्धि: कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की अपेक्षाकृत अधिक उपज।
	• ब्रिटिश नीति का शायद ही कोई उपयोग था क्योंकि खाद्य फसलों के उत्पादन के बजाय, नकदी फसलों का उत्पादन किया गया था, जिनका उपयोग अंततः इंग्लैंड में लगे औद्योगिक कारखानों में किया जाता था।
	• सिंचाई के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई, लेकिन भारत की कृषि में सीढ़ीदार, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी के विलवणीकरण में निवेश की कमी थी।

औद्योगिक क्षेत्र	• औपनिवेशिक शासन में भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकसित नहीं कर सका।
	• देश के हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट आई और कोई आधुनिक औद्योगिक आधार विकसित नहीं हो सका।
	• नीति के पीछे ब्रिटेन का उद्देश्य:
	  ○ ब्रिटेन में विकसित होने वाले आधुनिक उद्योगों के लिए भारत को महत्वपूर्ण कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे।
	  ○ उन उद्योगों के तैयार उत्पादों के लिए भारत को एक विशाल बाजार में बदलना ताकि उनका निरंतर विस्तार उनके गृह देश ब्रिटेन के अधिकतम लाभ के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
	• नीतियों का प्रभाव
	  ○ हस्तशिल्प उद्योग की गिरावट के कारण भारी बेरोजगारी

	○ भारतीय उपभोक्ता बाजार में माँग स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति से वंचित थी जिसके कारण ब्रिटेन से सस्ते विनिर्मित वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई। ○ आधुनिक उद्योग की शुरुआत: उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान, आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ें जमाना शुरू कर दिया लेकिन इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। ○ सूती वस्त्र मिलें: भारतीयों का वर्चस्व ■ स्थान: महाराष्ट्र और गुजरात, ○ जूट मिलें: विदेशियों का प्रभुत्व ■ स्थान: बंगाल ○ लौह और इस्पात उद्योग: 20वीं सदी की शुरुआत में आए। ■ 1907: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) की स्थापना हुई। ○ अन्य उद्योग: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि उद्योगों का उदय हुआ।
विदेशी व्यापार	• अंग्रेजों द्वारा उत्पादन, व्यापार और शुल्क की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार का ढाँचा, संरचना और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। • अंग्रेजों ने भारत के आयात और निर्यात पर एकाधिकार बनाए रखा। • औपनिवेशिक काल के दौरान बड़े पैमाने पर निर्यात अधिशेष उत्पन्न हुआ था • उनकी नीतियों का प्रभाव: भारत कच्चे उत्पाद रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट आदि जैसे प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बन गया और ब्रिटिश कारखानों में बनी हल्की मशीनरी व सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी वस्तुओं का आयातक बनकर रह गया। • स्वेज नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और तेज हो गया।

	• निर्यात अधिशेष उत्पादन ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। • कई आवश्यक वस्तुएँ जैसे खाद्यान्न, कपड़े, मिट्टी का तेल आदि की घरेलू बाजार में उपलब्धता कम हो गई। • इसके परिणामस्वरूप भारत में सोने या चाँदी का कोई प्रवाह नहीं हुआ, बल्कि इसका उपयोग ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यालय द्वारा किए गए खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता था व अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध पर खर्च किया जाता था। • इन सब के कारण भारतीय धन की निकासी हुई।
जनसांख्यिकीय दशा	• पहली जनगणना: 1881 • भारत की जनसंख्या वृद्धि में असमानता थी। • 1921 तक भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था। • 1921 के बाद संक्रमण का दूसरा चरण शुरू हुआ। • इस स्तर पर न तो भारत की कुल जनसंख्या और न ही जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक थी। • सामाजिक विकास संकेतक: ○ समग्र साक्षरता स्तर: 16% से कम ○ महिला साक्षरता स्तर: 7% ○ जनसंख्या के बड़े हिस्से तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। ○ जल और वायु जनित रोग बड़े पैमाने पर थे। ○ कुल मृत्यु दर बहुत अधिक थी। ○ शिशु मृत्यु दर: 218 प्रति हजार जबकि वर्तमान शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार है। ○ जीवन प्रत्याशा: 32 वर्ष वर्तमान 69 वर्षों के विपरीत। • व्यापक गरीबी: उस समय की भारत की जनसंख्या की दशा और ख़राब हो गई।
व्यावसायिक संरचना	• कृषि क्षेत्र: कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा 70-75% के उच्च स्तर पर बना रहा।

	• विनिर्माण क्षेत्र: कार्यबल के 10% हिस्से को रोजगार मिल पा रहा था। • सेवा क्षेत्र: इसमें कार्यबल का 15-20% हिस्सा शामिल था। • क्षेत्रीय भिन्नता का विकास: तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी, बॉम्बे और बंगाल के कुछ हिस्सों में कृषि क्षेत्र पर श्रमबल की निर्भरता में गिरावट देखी गई, साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि हुई। • उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में एक ही समय के दौरान कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।
आधारिक संरचना	• रेलवे, बंदरगाह, जल परिवहन, डाक और तार जैसी सुविधाओं हेतु बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ। • सड़कें: ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत में निर्मित सड़कें आधुनिक परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं थी अर्थात नई सड़कों का निर्माण किया गया। ○ उद्देश्य: भारत के भीतर सेना को संगठित करने और ग्रामीण इलाकों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए इन्हें दूर इंग्लैंड या अन्य आकर्षक विदेशी गंतव्यों में भेजने के लिए। • रेलवे: अंग्रेजों द्वारा 1850 में भारत में शरू की गई और इसे उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। ○ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: ○ इसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने और भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को कम में सक्षम बनाया। ○ इसने भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया जिसने भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ○ भारत के निर्यात की मात्रा में निस्संदेह विस्तार हुआ लेकिन इसका लाभ शायद ही कभी भारतीय लोगों को मिला हो। ○ रेलवे की शुरुआत के कारण भारतीय लोगों को जो सामाजिक लाभ मिला, वह देश के भारी आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक था। • अंतर्देशीय व्यापार और समुद्री मार्ग ○ अंग्रेजों के ये उपाय संतोषजनक नहीं थे। ○ अंतर्देशीय जलमार्ग भी अलाभकारी साबित हुए जैसे उड़ीसा तट पर तटवर्ती नहर के मामले में। • टेलीग्राफ सिस्टम: भारत में विकसित टेलीग्राफ की महंगी प्रणाली की शुरूआत ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य की पूर्ति की। • डाक सेवाएँ : उपयोगी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के बावजूद अपर्याप्त बनी रहीं।

स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था

1950	• आर्थिक विकास की एक विशेष रणनीति को अपनाना। ○ तेजी से औद्योगीकरण: केंद्र द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना को लागू करना। ○ इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में संसाधन जुटाना और उन्हें बड़े औद्योगिक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निर्माण में निवेश करना निहित था। • चुने गए उद्योग: स्टील, रसायन, मशीन और उपकरण, इंजन, बिजली। • सार्वजनिक उद्यमों के निर्माण के लिए निवेश का निर्देश दिया गया। • लक्ष्य: सार्वजनिक स्वामित्व के तहत उत्पादक संसाधनों के एक बड़े हिस्से को लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करके "समाज के समाजवादी पैटर्न" की स्थापना करना। • स्वतंत्र भारत में नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी।

नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था

योजनाबद्ध या समाजवादी अर्थव्यवस्था	मिश्रित आर्थिक प्रणाली

• एक आर्थिक प्रणाली जहाँ सरकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करती है।
• कभी-कभी इसे कमांड इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है।
• सरकार फैसला करती है :
  ○ किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है,
  ○ उत्पादन और वितरण विधि,
  ○ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें
• सरकार : केंद्रीय योजनाकार, नियामक और नियंत्रक।
• उदाहरण : उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया और क्यूबा।
• चीन में एक कमांड अर्थव्यवस्था थी।
  ○ साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों आदर्शों वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ने से पहले।
	• कमांड और फ्री-मार्केट सिस्टम दोनों की विशेषताएँ।
	• आंशिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित और आंशिक रूप से ही मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर आधारित।
	• दुनिया की अधिकांश महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएँ अब मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं,
	  ○ समाजवाद और पूंजीवाद के संयोजन के तहत संचालित,
	  ○ राजकोषीय या मौद्रिक नीतियों का उपयोग
	  ○ आर्थिक मंदी के दौरान विकास को प्रोत्साहित करने के लिए
	• मिश्रित आर्थिक प्रणाली में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निहित हैं।
	• एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सीमित सरकारी विनियमन।

2 CHAPTER अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत

सूक्ष्म और स्थूल अर्थव्यवस्था

सूक्ष्म अर्थव्यवस्था	स्थूल अर्थव्यवस्था
• व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। माँग और आपूर्ति, साथ ही अन्य कारक जो मूल्य स्तरों को प्रभावित करते हैं। • संभावित निवेशकों द्वारा निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। • एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को दर्शाता है। • यह भविष्यवाणी भी करता है कि भविष्य में किन वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक माँग होगी। • प्रोफेसर राग्नार फ्रिस्क ने सूक्ष्मअर्थशास्त्र शब्द दिया।	• इस बात का अध्ययन करता है कि देश और सरकारें व्यावसायिक निर्णय कैसे लेते हैं। • अर्थव्यवस्था की दिशा और प्रकृति को समझने के लिए ऊपर से नीचे तक पूरी खोज करती है। • आर्थिक और राजकोषीय नीति का विश्लेषण करने की एक विधि है। • सुनिश्चित करती है कि देश के आर्थिक संसाधनों का उपयोग उनकी पूरी क्षमता के लिए किया जाता है या नहीं। • जॉन मेनार्ड कीन्स को आम तौर पर समकालीन समष्टि आर्थिक सिद्धांत का जनक माना जाता है।

आर्थिक प्रणाली

- संसाधनों को आवंटित करने और पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं और समन्वय तंत्र का समूह

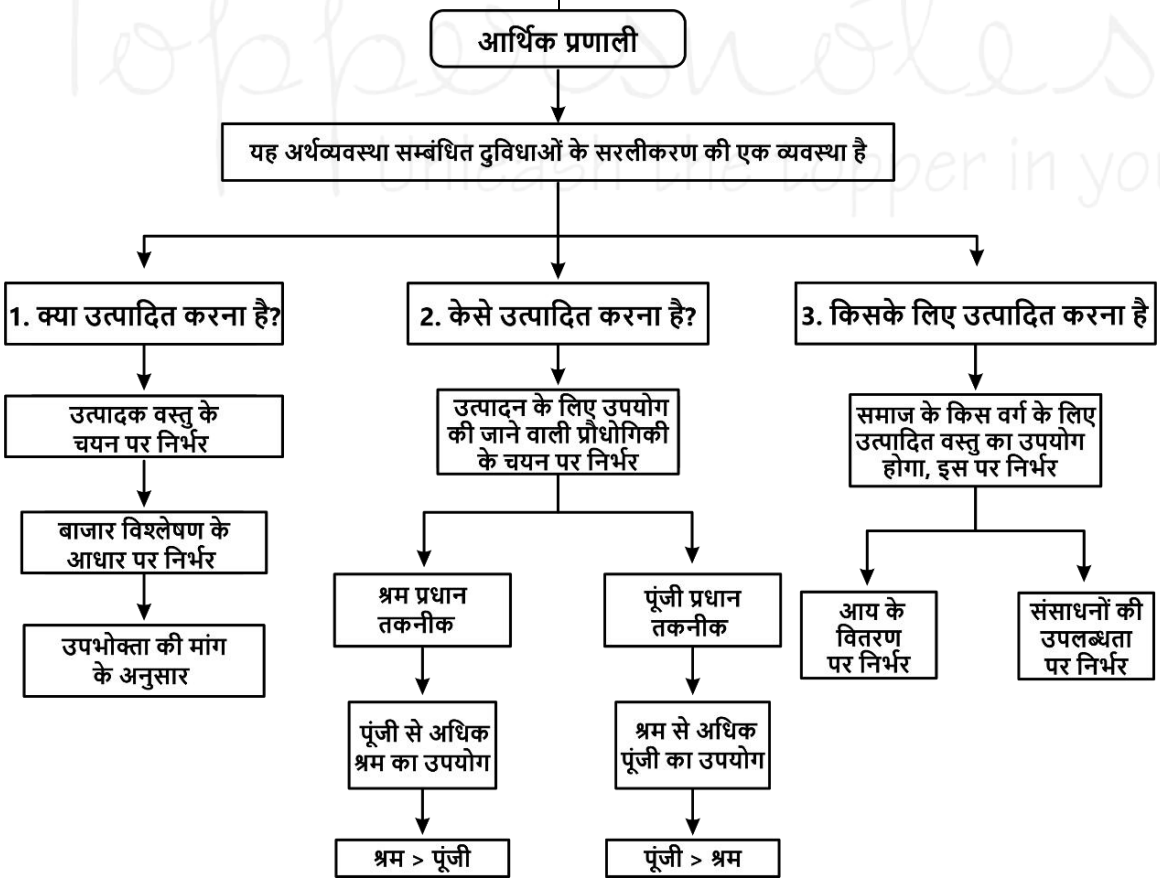

विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था	• एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न उत्पादों को व्यक्तियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। • उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। • माँग के बावजूद क्रय शक्ति की कमी के कारण माल का उत्पादन नहीं हो सकता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था	• सरकार तय करती है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पाद बनाया जाए। • व्यक्तिगत खरीददारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। • सिद्धांत रूप में समाजवाद के तहत साझा करना इस आधार पर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए, न कि वह जो वहन कर सकता है। • समाजवादी शासन में कोई अलग संपत्ति नहीं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था	• अर्थव्यवस्था कभी भी स्थायी रूप से राज्य के हस्तक्षेप या मुक्त बाजार की ओर नहीं झुकी बल्कि अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार हमेशा राज्य और बाजार का संतुलित मिश्रण रही।

पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर

मापदंड	पूँजीवादी अर्थव्यवस्था	समाजवादी अर्थव्यवस्था	मिश्रित अर्थव्यवस्था
स्वामित्व	निजी	सार्वजनिक	सार्वजनिक और निजी दोनों
मूल्य निर्धारण	बाजार की ताकतों से	केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा।	केंद्रीय योजना प्राधिकरण और बाजार शक्तियों द्वारा
उत्पादन का उद्देश्य	लाभ कमाना	सामाजिक कल्याण	निजी क्षेत्र में लाभ और सार्वजनिक क्षेत्र में कल्याण
सरकार की भूमिका	कोई भूमिका नहीं	पूर्ण नियंत्रण में	सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण भूमिका और निजी क्षेत्र में सीमित
प्रतिस्पर्द्धा	मौजूद	कोई प्रतियोगिता नहीं	केवल निजी क्षेत्र में
आय वितरण	बहुत असमान	बिल्कुल बराबर	काफ़ी असमानताएँ मौजूद होती हैं

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

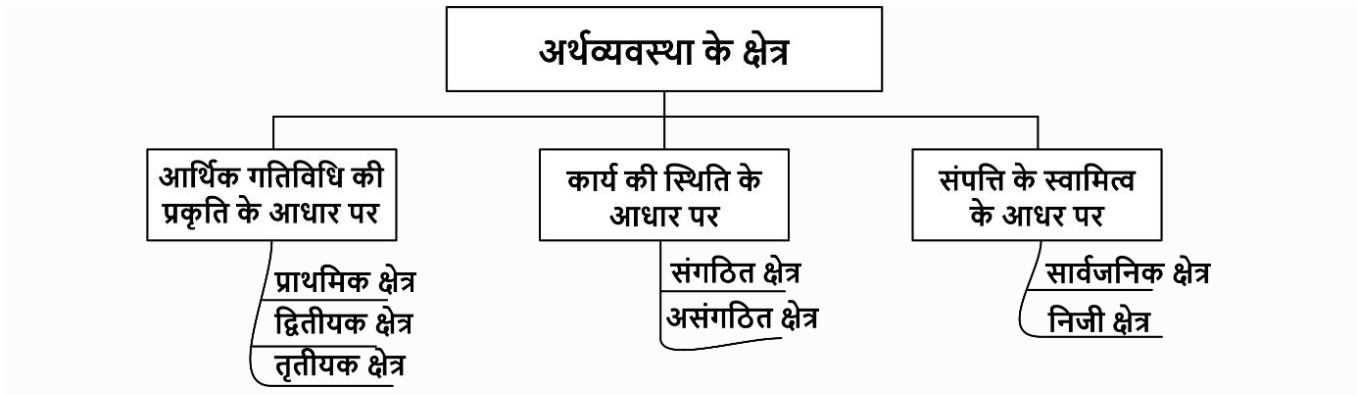

आर्थिक गतिविधि की प्रकृति पर आधारित

प्राथमिक क्षेत्र

- प्राकृतिक संसाधनों की निकासी या कच्चे माल के निर्माण में शामिल उद्योग।
- उदाहरण के लिए कृषि, मछली पकड़ना और खनन आदि।

द्वितीयक क्षेत्र

- उपयोगी वस्तुओं या पूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में शामिल उद्योग
- जैसे: भारी और हल्के उद्योग (इस्पात, रसायन और ऑटोमोबाइल) (भोजन, परिधान, सौंदर्य प्रसाधन)।

तृतीयक क्षेत्र

- अन्य फर्मों या अंतिम उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करना।
- उदाहरण: खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य उद्योग

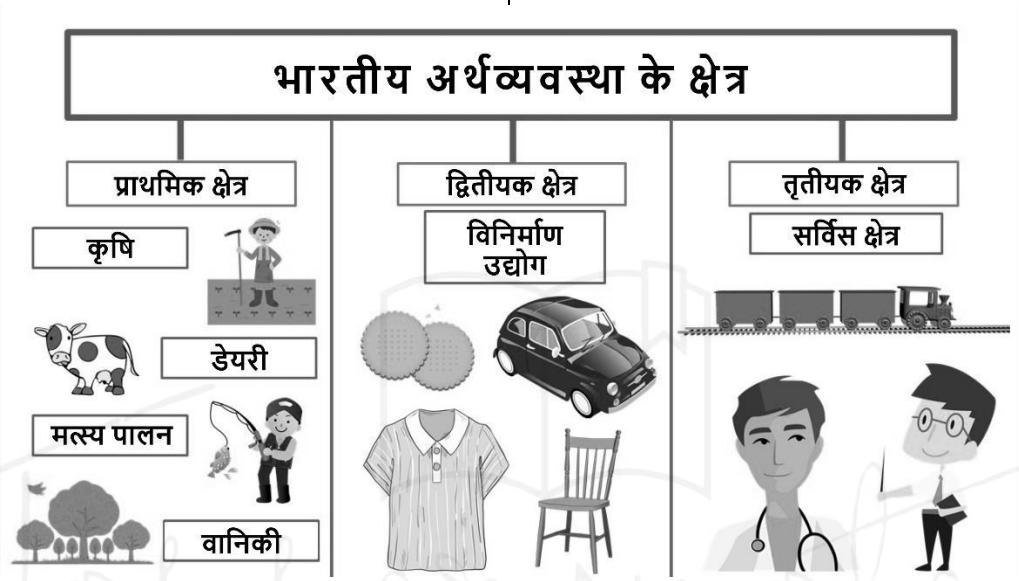

चतुर्थक क्षेत्र	• ज्ञान के निर्माण और प्रसार में निहित। • जैसे: अनुसंधान और विकास, शिक्षा आदि।
पंचम क्षेत्र	• किसी अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने का उच्चतम स्तर।
गुलाबी कॉलर नौकरियाँ	• वह नौकरी जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम या महिला-उन्मुख नौकरी माना जाता है। • अधिक पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। • जैसे: दाई, फूलवाला, डे केयर वर्कर, नर्स आदि।

कार्य की स्थिति पर आधारित

संगठित क्षेत्र

- उन उद्यमों या कार्यस्थलों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं।
- सरकार द्वारा पंजीकृत और इसके नियमों और विनियमों का पालन करना होता है जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में दिए गए हैं।

असंगठित क्षेत्र

- छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होती हैं। नियम और कानून हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है।
- कम वेतन वाली नौकरियाँ, अक्सर नियमित नहीं होती हैं।
- रोजगार सुरक्षित नहीं है और नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है।
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची- II में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित किसी भी अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया है।
- इसके अंतर्गत घर पर काम करने वाले कर्मचारी या स्वरोजगार करने वाले कर्मचारी या मजदूरी करने वाले कर्मचारी शामिल किए जाते हैं।

संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर

सार्वजनिक क्षेत्र

- स्वामित्व: सरकार के तहत।
- मुख्य रूप से सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से।
- जैसे: रेलवे, भारतीय डाक सेवाएँ, आदि।

निजी क्षेत्र

- स्वामित्व: निजी व्यक्तियों या कंपनियों के अधीन।
- उदाहरण: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) जैसी कम्पनियाँ निजी स्वामित्व वाली हैं।

सूर्योदय उद्योग

- वह औद्योगिक क्षेत्र जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन तेजी से उछाल का वादा करता है।
- उच्च विकास दर, उच्च स्तर के नवाचार और आम तौर पर इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जन जागरूकता होती है और निवेशक इसकी दीर्घकालिक विकास संभावनाओं से आकर्षित होते हैं।
- जैसे:
  - सूचना प्रौद्योगिकी
  - दूरसंचार क्षेत्र
  - स्वास्थ्य सेवा
  - आधारभूत संरचना क्षेत्र
  - खुदरा क्षेत्र
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
  - मत्स्य पालन

माँग आपूर्ति प्रबंधन

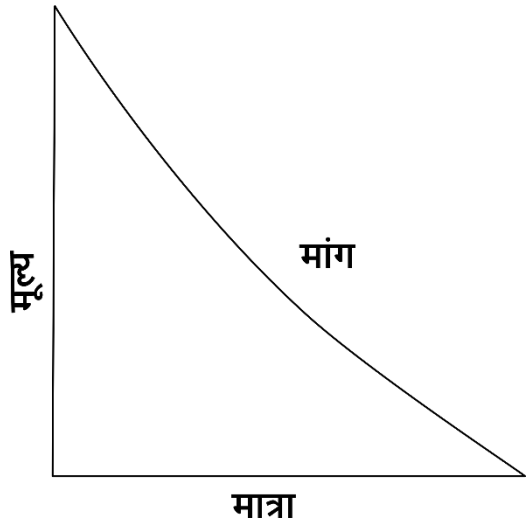

माँग वक्र: यह वस्तु की कीमत और उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय सीमा में उस वस्तु को खरीद पाने की क्षमता के मध्य सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है।यह वक्र वरीयताओं, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतों, अपेक्षाओं और खरीदारों की संख्या पर निर्भर करता है।

माँग के निर्धारक

- अच्छी कीमत
- क्रेता द्वारा उत्पाद की वरीयता या इच्छा का स्तर
- क्रेता की आय
- संबंधित उत्पादों की कीमतें :
  - स्थानापन्न उत्पाद (खरीदार की राय में उत्पाद के साथ सीधे प्रतिस्पर्द्धा; जैसे चाय और कॉफी)
  - पूरक उत्पाद (खरीदार की राय में वस्तु के साथ प्रयुक्त; जैसे कार और पेट्रोल)
- भविष्य की अपेक्षाएँ
  क्रेता की अपेक्षित आय।
  वस्तु का अपेक्षित मूल्य।

माँग में कमी करने वाले परिवर्तन

- स्थानापन्न वस्तु की घटी हुई कीमत
- पूरक वस्तु की बढ़ी हुई कीमत
- सामान्य वस्तु है तो आय में कमी
- आय में वृद्धि अगर अवर वस्तु है।

माँग की लोच

- मूल्य चर (P) में परिवर्तन के लिए मात्रा चर (Q) की संवेदनशीलता का एक उपाय
- लोच का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण है कि राजस्व कैसे भिन्न होगा क्योंकि यह इस मुद्दे का उत्तर देता है कि मूल्य में 1% परिवर्तन के लिए प्रतिशत के संदर्भ में मात्रा कितनी बदलेगी।
- बेलोचदार मांग वक्र अधिक है क्योंकि P में पर्याप्त परिवर्तन भी Q में थोड़ा परिवर्तन उत्पन्न करता है।
- जैसे: खाद्यान्न: अगर कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो भी लोग अपनी खपत कम नहीं करेंगे; और अगर P गिरता है, तो लोग अपनी खपत नहीं बढ़ाएंगे।

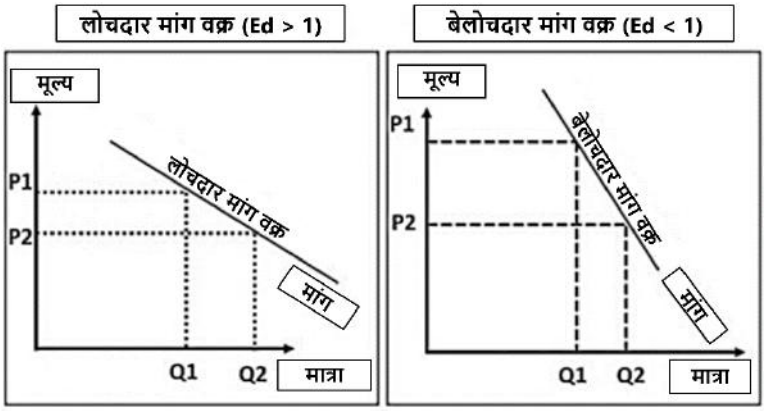

आपूर्ति क्या है?

- एक वस्तु की वह मात्रा जो एक कंपनी एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होती है।
- 'आपूर्ति वक्र' का पालन किया जाता है। कीमत जितनी अधिक होगी, कंपनी को उतना ही अधिक बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

वस्तु की आपूर्ति बढ़ेगी:

- लाभ = कुल राजस्व - कुल लागत
- राजस्व = उत्पादन की बिक्री के माध्यम से प्राप्त धन = मूल्य (पी) x मात्रा (क्यू)
- यदि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, तो उच्च मूल्य के परिणामस्वरूप लाभ होगा।
- माँग का नियम: जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है, अनुरोधित मात्रा (Qd) घटती जाती है।
- आपूर्ति का नियम: जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है, वैसे-वैसे प्रदान की गई मात्रा भी होती है (Qs)

आपूर्ति के निर्धारक

कर	• जैसे-जैसे कर बढ़ता है, आपूर्ति गिरती है और आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। • विनिर्माण लागत और लेवी में वृद्धि का समान प्रभाव पड़ेगा। • 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने के लिए करों में कटौती की। • इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति वक्र दायीं ओर खिसक गया।
उत्पादन लागत	• यदि उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो आपूर्ति भी बढ़ती है। • आपूर्ति वक्र में बदलाव: जैसे-जैसे विनिर्माण लागत बढ़ती है, प्रदान की गई राशि कम हो जाती है और आपूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है।
	• जब उत्पादन की लागत गिरती है, तो उत्पादित मात्रा में वृद्धि होती है। • आपूर्ति वक्र दाईं ओर तिरछा होगा।
कंपनी के लक्ष्य	• लाभ हमेशा किसी कंपनी का मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। • इसका उद्देश्य बिक्री बढ़ाना या सामाजिक कल्याण में सुधार करना हो सकता है। • इस परिदृश्य में आपूर्ति बढ़ने पर आपूर्ति वक्र दाईं ओर झुकता है। • अच्छी बारिश से भी आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है।

आपूर्ति की लोच

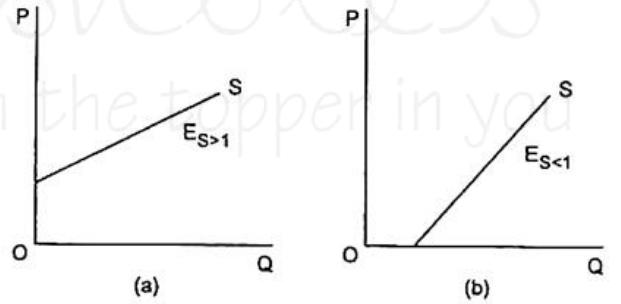

"कीमत में बदलाव के लिए आपूर्ति की गई मात्रा की प्रतिक्रिया"

- उच्च लोच: यदि परिवर्तन तीव्र है
- लोच (एस): (आपूर्ति की मात्रा में% परिवर्तन) / (कीमत में% परिवर्तन)
- यदि Es>1: आपूर्ति लोचदार है
- यदि Es<1: आपूर्ति बेलोचदार है

आपूर्ति की लोच के निर्धारक

- समग्र निर्धारक विकल्प है: फर्म के पास जितना अधिक विकल्प, उतना अधिक लोच
  - उदाहरण के लिए जल्दी खराब होने वाली वस्तु की मात्रा: फर्म के पास स्टोर करने का कोई विकल्प है/विकल्प नहीं है; किसी भी कीमत पर बेचना होगा।
  - कृषि वस्तुओं के लिए: बेलोचदार आपूर्ति।

बाजार संतुलन

- आवश्यक मात्रा = उपलब्ध मात्रा.
  संतुलन: माँग और आपूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन का बिंदु।
- आदर्श स्थिति: वह स्थिति जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों अधिकतम उपयोगिता और संतुष्टि प्राप्त करते हैं।
- बाजार दो तरह के लोगों से मिलकर बनता है: क्रेता और विक्रेता
  - खरीदार अपने आनंद को बढ़ाने के लिए सस्ता मूल्य निर्धारण चाहते हैं।
  - विक्रेता अधिक मुनाफा चाहते हैं।
- यदि कीमत संतुलन स्तर से कम हो जाती है, तो कमी हो जाएगी।
- स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के हितों में कीमत बढ़ेगी।
  - संतुलन मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक आपूर्ति होगी, जिससे आपूर्तिकर्ताओं को अपने सभी सामान बेचने के लिए अपनी कीमतें कम करनी होंगी।

उपभोक्ता संतुलन: वह स्थिति जिसमें एक उपभोक्ता अपनी आय को कई वस्तुओं पर इस तरह खर्च करता है कि उसे अधिकतम सुख प्राप्त हो।

प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम: वह बिंदु जिस पर वह सबसे अधिक लाभ अर्जित करते हुए सबसे अधिक उत्पादन करता है।

मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत

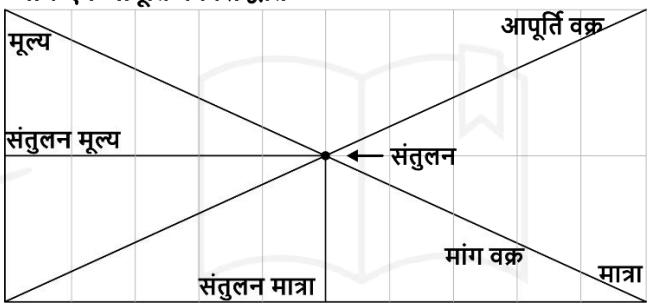

मांग और आपूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव

आपूर्ति/मांग में परिवर्तन	मूल्य पर प्रभाव	उदाहरण
जब आपूर्ति बढ़ती है	कीमतों में कमी	मंडियों में कृषि उपज की आपूर्ति में वृद्धि
जब डिमांड बढ़ती है	कीमतें बढ़ जाती हैं	नवरात्रि के दौरान फलों की कीमत

3 CHAPTER राष्ट्रीय आय

- **राष्ट्रीय आय:** मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद, एक लेखा वर्ष के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
  - यह कारक लागत (FC) पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) है।
  - इसमें कर, मूल्यह्रास और गैर-कारक इनपुट (कच्चा माल) शामिल नहीं है।
- देश की प्रगति के निर्धारण में भी उपयोगी है।
- इसमें निहित हैं: मजदूरी, ब्याज, किराया और उत्पादन के घटकों द्वारा प्राप्त लाभ जैसे: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता।
- **घरेलू आय**: मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
  - यह कारक लागत पर एनडीपी(NDP) है।
- एनएनपी(NNP) और एनडीपी(NDP) दोनों को स्थिर कीमतों (वास्तविक आय) या बाजार मूल्य (नाममात्र आय) पर मापा जा सकता है।
- **राष्ट्रीय आय:** घरेलू आय + एनएफआईए

कुछ महत्वपूर्ण शर्तें	
कारक लागत(FC)	• किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या उपयोग किए गए उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत।
मूल क़ीमत(BP)	• जब किसी सेवा या वस्तु के उत्पादन के कारक लागत में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाए जाने वाले सभी करों को जोड़कर उसमें से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली सभी सब्सिडियों को घटाया जाता है तब प्राप्त मूल्य मूल कीमत कहलाता है। • मूल कीमत(BP)= कारक लागत (FC) + उत्पादन कर(PT) - उत्पादन सब्सिडी(PS)
बाजार मूल्य(MP)	• जिस कीमत पर कोई वस्तु बाजार में बेची जाती है। इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज, इनपुट मूल्य, लाभ और उत्पादन की अन्य लागतें निहित हैं। • सरकार द्वारा लगाए गए कर और सरकार द्वारा प्रदान की गई उत्पादन सब्सिडी भी निहित है। • बाज़ार मूल्य(MP)= मूल कीमत(BP)+ उत्पाद कर(PT) - उत्पाद सब्सिडी(PS) या बाज़ार मूल्य(MP)= कारक लागत(FC)+ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर(NIT)
मूल्यह्रास	• मूल्यह्रास का अर्थ पूंजीगत संपत्ति के मूल्य में समय के अनुसार आने वाली कमी से है। मूल्यह्रास के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे- • सम्पत्ति का पुराना हो जाना (मशीनरी/फर्नीचर) • उसका प्रचलन से बाहर हो जाना • तकनीकी में बदलाव आना / अपग्रेड होना
स्थानान्तरण भुगतान	• एक मौद्रिक भुगतान जिसके लिए कोई वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है। • स्थानीय, राज्य और संघीय सरकारों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को धन के पुनर्वितरण के प्रयासों को आमतौर पर हस्तांतरण भुगतान के रूप में संदर्भित किया जाता है। • सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी बीमा जैसे हस्तांतरण भुगतान संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हैं। • स्थानांतरण भुगतान का उपयोग आमतौर पर कॉर्पोरेट, राहत पैकेज और सब्सिडी का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय आय के पहलू

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

- किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- आर्थिक संकेतक किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- नियमित अवधियों पर अनुमानित (जैसे- त्रैमासिक / वार्षिक)
  - भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उत्पादन क्षेत्र में शामिल हैं-
  - किसी देश की भौगोलिक सीमाएँ जिसमें उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) शामिल हैं। (200 समुद्री मील या 360 किलोमीटर तक)
  - विभिन्न देशों में एक देश का दूतावास
  - वाहन जैसे जहाज, विमान आदि जिस देश में पंजीकृतहोते हैं, वे उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत माने जाते हैं।
- उत्पाद में निहित हैं: देश के घरेलू क्षेत्र में सामान्य निवासियों और अनिवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ।
  - विदेश से शुद्ध कारक आय (NFIA) शामिल नहीं है।
- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा गणना की जाती है।
- 'मात्रात्मक अवधारणा' और अर्थव्यवस्था की आंतरिक ताकत को इंगित करता है।
- आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा सदस्य की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

जीडीपी = खपत + निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात - आयात

सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए तरीके

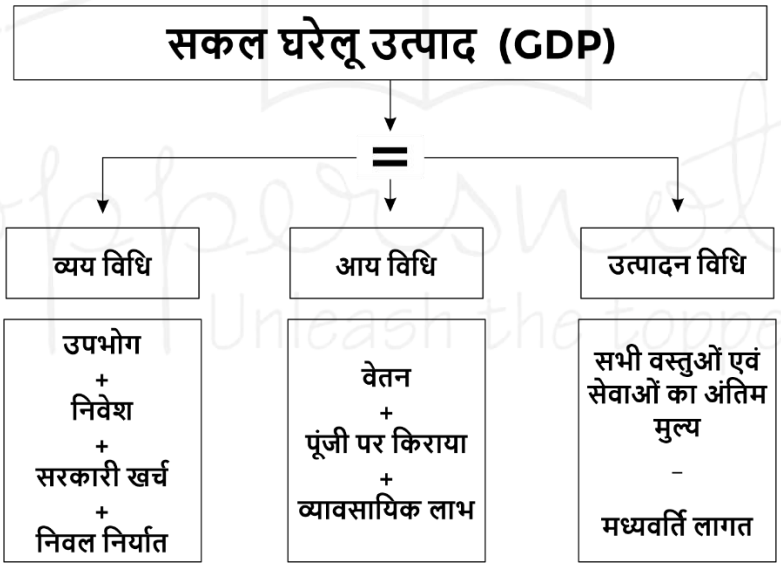

सांकेतिक जीडीपी	वास्तविक जीडीपी
• देश के भीतर उत्पादित कुल वित्तीय व्यवसाय मूल्य। • मुद्रास्फीति के बिना समायोजित। • चालू वर्ष की कीमतों पर। • उच्च मूल्य • एक वर्ष की तिमाहियों की तुलना करता है। **सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद = चालू वर्ष में उत्पादन ✖ चालू वर्ष में मूल्य** • अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है।	• जीडीपी मीट्रिक समायोजित : सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के साथ। • मुद्रास्फीति से समायोजित • नियमित कीमतों पर • कम मूल्य • दो या दो से अधिक वित्तीय वर्ष की तुलना करता है। **वास्तविक जीडीपी = चालू वर्ष में उत्पादन ✖ आधार वर्ष मूल्य** • केवल वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन के आँकड़े सम्मिलित किये जाते हैं।

जीडीपी अपस्फीतिकारक(GDP Deflator)

- उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है।
- मुद्रास्फिति माप संकेतक है जो CPI सूचकांक की तुलना में अधिक व्यापक है।

जीडीपी डिफ्लेटर =सांकेतिक जीडीपी / वास्तविक जीडीपी

जीडीपी विकास दर:

- मापता है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है।
- जीडीपी में लगातार दो वर्षों या तिमाहियों में परिवर्तन को मापता है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर = 100 x [(जीडीपी चालू वर्ष/तिमाही – जीडीपी पिछला वर्ष/तिमाही)/जीडीपी पिछला वर्ष/तिमाही]

- वास्तविक आर्थिक विकास दर क्रय शक्ति को ध्यान में रखती है और इसमें मुद्रास्फीति-समायोजित होती है।

कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपीएफसी)

- कारक लागत एक वस्तु के उत्पादन की लागत है। इसमें भूमि, श्रम, पूँजी और उत्पादक के मुनाफे की लागत शामिल होती है।

बाजार मूल्य पर जीडीपी (GDPMP)

- बाजार मूल्य में साधन लागत के साथ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। (शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कुल अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का अंतर)

GDPMP = GDPFC + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

सकल मूल्य वर्धित(GVA)

- इसमें GDP की गणना बाज़ार मूल्य पर की जाती है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न चरणोंको शामिल किया जाता है।
- इसमें दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं के आधार पर गणना की जाती है।

GVA = GDP + सब्सिडी - कर

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)

- किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर सृजित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल संपत्ति।
- राष्ट्रीय पूंजी परिसंपत्तियों जैसे मशीनरी, घरों और कारों के मूल्यह्रास का मूल्य एनडीपी की गणना के लिए जीडीपी से घटाया जाता है।
- अन्य कारण: परिसंपत्ति का अप्रचलन और पूर्ण विनाश को भी एनडीपी द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद(NDP) =सकल घरेलू उत्पाद (GDP) –मूल्यह्रास.

- **महत्व**
  - अर्थव्यवस्था को मूल्यह्रास के कारण हुए नुकसान की ऐतिहासिक स्थिति को समझना।
  - तुलनात्मक अवधि में उद्योग और व्यापार में मूल्यह्रास की क्षेत्रीय स्थिति को समझना और विश्लेषण करना।
  - आर और डी के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक समय अवधि में मूल्यह्रास के स्तर को ठीक करने का प्रयास किया है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- किसी देश में नागरिकों और उद्यमों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वे कहीं भी उत्पादित हों।
- यह विदेशों से अपनी आय के साथ जोड़ा गया देश का सकल घरेलू उत्पाद है।
- 'विदेश से आय' में निम्नलिखित शामिल हैं :
  - व्यापार संतुलन: किसी देश के कुल निर्यात और आयात का वर्ष के अंत में शुद्ध परिणाम।
  - बाहरी ऋणों पर ब्याज: देश द्वारा उधार दिए गए धन पर ब्याज की शेष राशि और उस धन पर ब्याज जो उसने अन्य देशों से उधार लिया है।
    - भारत हमेशा विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक 'शुद्ध ऋणी' रहा है।
  - निजी प्रेषण: विदेशों में काम कर रहे भारतीयों (भारत में) और भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिकों (अपने गृह देशों में) द्वारा 'निजी हस्तांतरण' का खाता।

GNP(Y) =उपभोग व्यय (सी) + निवेश (आई) + सरकारी व्यय (जी) + शुद्ध निर्यात (एक्स) + विदेश से शुद्ध आय (Z).

Y = C + I + G + X + Z

- **जीएनपी के कारक**: उपकरण, मशीनरी, कृषि उत्पादों और करों और कुछ सेवाओं जैसे परामर्श, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी वस्तुओं का निर्माण।
- सेवाओं को वितरित करने की लागत की गणना नहीं की जाती है।
- जब कोई नागरिक दोहरी नागरिकता रखता है तो प्रति व्यक्ति जीएनपी का उपयोग देश-दर-देश के आधार पर जीएनपी की गणना के लिए किया जाता है।
- उस स्थिति में, उनकी आय को प्रत्येक देश के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में दो बार गिना जाता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को हटाकर प्राप्त मूल्य NNP कहलाता है।
- यह निर्धारित करता है कि एक देश एक विशिष्ट समय अवधि में कितना उपभोग कर सकता है।

NNP = GNP –मूल्यह्रास
or
NNP = GDP + विदेशों से आय - मूल्यह्रास

- जब किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) गिरता है,
  - व्यवसाय उन उद्योगों में स्थानांतरित होने पर विचार करते हैं जिन्हें मंदी-अभेद्य माना जाता है।

निजी आय(PI)	• किसी देश के नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से अर्जित की गई धन राशि। • जैसे रोजगार से प्राप्त धन, निवेश द्वारा भुगतान लाभांश और वितरण, संपत्ति के स्वामित्व से प्राप्त किराया, और उद्यमों से लाभ साझा करना। • अधिकांश मामलों में व्यक्तिगत आय पर कराधान लगाया जाता है। **PI = राष्ट्रीय आय – अविभाजित लाभ– परिवारों द्वारा प्रदत्त शुद्ध ब्याज – कॉर्पोरेट टैक्स + सरकार और फर्मों से परिवारों को भुगतान हस्तांतरण**
व्यक्तिगत प्रयोज्य आय(PDI)	• परिवारों के लिए उपलब्ध आय जिसे वे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। • करों के भुगतान और अन्य गैर-कर भुगतान के बाद उपलब्ध आय। **PDI = PI – निजी कर भुगतान– गैर-कर भुगतान**
राष्ट्रीय डिस्पोजेबल आय	• संस्थागत क्षेत्रों की सकल (या शुद्ध) प्रयोज्य आय का योग। **सकल (या शुद्ध) एनडीआई = सकल (या शुद्ध) राष्ट्रीय आय (बाजार कीमतों पर)-अनिवासी इकाइयों को देय वर्तमान स्थानान्तरण**

राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके

आय विधि	• स्वरोजगार द्वारा सभी उत्पादन कारकों (किराया, वेतन, ब्याज, लाभ) और मिश्रित-आय को जोड़कर अनुमानित। • हम इस प्रक्रिया का उपयोग करके किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त सभी शुद्ध आय भुगतान को जोड़ते हैं। • उत्पादन के सभी कारकों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। ○ उदाहरण: शुद्ध किराया, मजदूरी, ब्याज, और मुनाफा। • हस्तांतरण भुगतान के रूप में प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं की जाती। **शुद्ध राष्ट्रीय आय = कर्मचारियों का मुआवजा + मिश्रित परिचालन अधिशेष (W +R +P +I) + शुद्ध आय + विदेश से शुद्ध कारक आय जहाँ,** ■ **W** = Wages and salaries ■ **R** = Rental Income ■ **P** = Profit ■ **I** = Mixed Income
उत्पाद/मूल्य वर्धित विधि	• एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में बाजार कीमतों पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। • जीएनपी की गणना करने के लिए, ○ सभी उत्पादक गतिविधियों से डेटा एकत्र किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। इसमे निम्नलिखित शामिल हैं : ■ कृषि माल, ■ खनिज, और ■ औद्योगिक उत्पादों ■ परिवहन, बीमा, संचार, वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों आदि द्वारा किए गए उत्पादन में योगदान। **राष्ट्रीय आय = जीएनपी - पूंजी की लागत - मूल्यह्रास - अप्रत्यक्ष कर**

व्यय विधि	• राष्ट्रीय आय को व्यय प्रवाह के रूप में मापा जाता है।
	• इसमें समाज द्वारा कुल व्यय का योग शामिल है :
	  ○ निजी उपभोग व्यय,
	  ○ शुद्ध घरेलू निवेश,
	  ○ वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च, और
	  ○ शुद्ध विदेशी निवेश।
	राष्ट्रीय आय = राष्ट्रीय उत्पाद = राष्ट्रीय व्यय

आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति

- **गठन:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा।
- **अध्यक्ष**: पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद्
- **कार्य**
  - विश्लेषण और विकास : रोजगार, उद्योग और सेवाओं पर देश का सर्वेक्षण
  - डेटा स्रोतों, संकेतकों और परिभाषाओं के वर्तमान ढ़ांचे को देखना
    - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, समय-समय पर श्रम बल सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों के लिए।
  - 4 स्थायी समितियों श्रम बल सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, सेवा क्षेत्र, और अनिगमित क्षेत्र की फर्मों को SCES में समाहित किया जाएगा।
  - 108 अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत में सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रभावित करने में "राजनीतिक भागीदारी" पर चिंता व्यक्त की।
    - सांख्यिकीय संगठनों की "संस्थागत स्वतंत्रता" और अखंडता को बहाल करने की अपील की।